0k"ki % 42(vad % 03 (ekp % 2020(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स

चेन्नै; 23–27 जनवरी, 2020

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स की जनसभा के मंच पर राष्ट्रीय नेतृत्व

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स की जनसभा में उमड़ा जनसमूह

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो आदि कृपया इस मेल पर भेजें– *citujournals@gmail.com*

सीटू का देशव्यापी अभियान

सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स ने फरवरी–मार्च 2020 के दौरान सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ कार्यस्थलों और घर–घर देशव्यापी अभियान का आह्वान किया। इस अभियान का समापन 23 मार्च 2020 को भगत सिंह के शहादत दिवस पर विशाल जिला स्तरीय रैलियों में भारत के संविधान की प्रतिज्ञा लेने के साथ होना है। और इसमें किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और अन्य सामाजिक संगठनों सहित सभी तबकों के जन और सामाजिक संगठनों को शामिल करना है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रतिज्ञा लेना

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को **संप्रभुता-सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य** बनाने के लिए और अपने सभी नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा** में, आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 को एतद्द्वारा **इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित** और **आत्मार्पित करते** हैं।

सम्पादकीय

मजदूरवर्ग के आंदोलन के चरित्र में आये बदलाव

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

मार्च 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के. हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे. एस. मजुमदार~~

सदस्य

~~तपन सेन,~~

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

ftu rd ugh igp

mu rd igpr g,

&d- geyrk 5

8 tuojh 2020 dh vke gMrky 7

Je e=h d lkFk dæh; VsM

;fu;uk dh cBd

& vkj- d#eyk;u 17

m|kx ,o {k= & ry o xl

nk fnu dh jk"V0;kih gMrky

& Lon'k no jk; 19

lekurk d fy, vkj HknHkko

d f[kykQ yMk

& ,-vkj- flU/k 23

miHkkDrk eY; lpdkd 26

8 tuojh 2020 dk g;h n'kHkj d etnjk dh vke gMrky igy dh gMrkyk d edkcy flQ bldh rhork vkj foLrkj d ekey e gh ugh cfYd fiNyh lky 8&9 tuojh dk g;h n'k0;kih gMrky l vknkyu d pfj= d ekey Hkh lkQ rkj l fHkUu vkj vyx FkhA ,d Økfrdkjh VsM ;fu;u gkuu d ukr lhV d fy, t:jh gk tkrk g fd og vknkyu d pfj= e vk;s bu cnykok dk nt djA

T;k&T;k] nfu;k Hkj e] ldVxLr i thokn viu ck> dk etnjk vkj vke turk ij Mkyu dh fue'e dkf'k'k dj jgk g] R;k&R;k gkykr rth d lkFk cny jg gA viu euk dk vf/kdre dju dh bl /ku e i thokn viu foHkktudkjh ,tM dk vkx j[kdj ihfMr turk d çfrjk/k vknkyu dk detkj vkj foHkkftr dju dh dkf'k'k dj jgk gA

etnjk vkj egurh voke d thou vkj thou;kiu ij c< geyk dh otg l oxh; vrfojk/k fuf'pr gh rh[k g, g(etnjk dh lkekftd lj{kk ij gey] etnjk d dkuuh rFkk ijEijkxr vf/kdkjk ij gey] m|kx cnh vkj c<rh jktxkjghurk] fjd,M cjktxkjh] yxkrkj c<rh egxkb d lkFk n'k dh vFk0;oLFkk e enh d #>ku n'k dk piV e y jg g(njckjh i thokn dh [kkfrj /kMk/kM futhdj.k dh efge bl d vykok g(lh,,] ,uvkjlh vkj ,uihvkj tl dkek d tfj; Hkkjr d lfo/kku dh /kefujik{k cfu;kn ij fur u, gey tkjh g(turkf=d lLFkkvk vkj ijEijkvk ij ,ykfu;k rkuk'kkgh gey fd; tk jg g(n'k d l?kh; <kp ij gey gk jg g(lkekT;oknijLrh d #>ku n'k dk ekrgr jkT; cuku dh vkj c<r fn[kk jg g(n'k e dyhur=h lÙkk mHkkju d tru tkjh gA

bl lcd f[kykQ turk dk fojk/k c< jgk gA bu fojk/k dk;okfg;k e etnjk] fdlkuk dh fo'kky Hkkxhnkfj;k vkj [kklrkj l Nk=k] ;okvk] efgykvk dh fgLlnkfj;k ftruh c<p< dj gk jgh g] o gky d nkj e vHkrio gA

;s lkjs vknkyu ,d 0;kid tuoknh vknkyu e lekfgr gku dh fn'kk e c< jg gA bldh /ktk 8 tuojh 2020 dh etnjk dh vke gMrky turk d fofo/k fgLlk dh Hkkxhnkjh rFkk vU; rcdk d vkUnkyuk e etnjk dh f'kjdr d :i e lkQ lkQ uek;k fn[kh gA

gj Lrj d lhV dk;drkvk d chp bl le>nkjh dk y tkuk vkj bl mldh pruk dk fgLlk cukuk vkt dh Qkjh t:jr gA lHkh bdkb;k] ;fu;uk] QMj'kuk dh lfefr;k rd bl y tk;k tkuk pkfg,A lhV lxBu d lkxBfud iumUe[khdj.k d dke dk Hkh rRdky djuk gkxk rkfd [kklrkj l lhV rFkk vkerkj l VsM ;fu;u vknkyu d nk;j l ckgj d etnjk dh fojkV rknkn l lokn fd;k tk ld] mud lkFk lkxBfud fj'r dk;e fd;s tk ld] gj Lrj d viu dk;drkvk d chp ,d lk>h vkj ,dtV le>nkjh fodflr dh tk ldA

साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन

ऑल इण्डिया पीस एण्ड सोलिडेरिटी ऑर्गेनाईजेशन (एआईपीएसओ) की एक संयुक्त बैठक; ऑल इण्डिया एग्रीकल्चर वर्कर्स फेडरेशन (एआईएडब्ल्यूयू); ऑल इण्डिया एन्टी–इम्पीलियस्ट फॉरम; ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए); अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस); ऑल इण्डियालॉयर्स यूनियन (एआईएलयू), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी); बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई), फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (आईपीटीए) और इंसाफ का आयोजन नई दिल्ली में बीटीआर भवन में 17 फरवरी 2020 को हुआ। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः

1. 24 और 25 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा का विरोध करना, क्योंकि यह भारतीय जनता के हितों के लिए हानिकारक है;
2. 24 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए, जनता के विशाल तबकों, जन संगठनों और सामाजिक आंदोलनों को शामिल करना है, जो हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा और हमारे देश की कृषि, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं;
3. भारत सरकार की अमेरिका–समर्थक नीतियों के हानिकारक प्रभाव की व्याख्या करते हुए जनता के बीच बड़े पैमाने पर प्रचार करके उन्हें विरोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लामबन्द करना है;
4. अमेरिका और भारत दोनों की सरकारों की एक जैसी अल्पसंख्यक विरोधी, प्रवासी–विरोधी, महिला–विरोधी, नस्लीय, सांप्रदायिक, जातिवादी और विभाजनकारी नीतियों को बेनकाब करना है;
5. सभी समान विचारधारा वाले, देशभक्त, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक संगठनों और व्यक्तियों से संपर्क करके उनसे विरोध में शामिल होने का अनुरोध करना है;
6. जनता में इन विचारों को फैलाने के लिए रचनात्मक और आकर्षक नारे, स्मति चिन्ह, कला रूपों और अभियान सामग्री को विकसित करें और सोशल मीडिया सहित सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें।

बैठक में शामिल संगठनों ने उन सभी संगठनों से भी अपील की है, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

नोटिस

सीटू सचिवमण्डल की मीटिंग

बीटीआर भवन, नई दिल्ली, 14–15 मार्च 2020

- एजेंडाः (1) सीटू की 16वीं कान्फ्रेन्स की समीक्षा; (2) 8 जनवरी, 2020 की आम हड़ताल की समीक्षा; (3) 31 मई, एवं 1–2 जून 2020 को कोलकाता में होने वाली सीटू की जनरल कौसिंल मीटिंग की तैयारी; (4) भविष्य की कार्रवाई; (5) अन्य कोई मुद्दा।
- इस बार जनरल काउंसिल की बैठक 30 मई 2020 को, कोलकाता में सीटू के स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के बाद होगी।
- वर्किंग वुमन कमेटी के पदाधिकारी स्तर की मीटिंग 13 मार्च को सुबह 11 बजे होगी।

तपन सेन, महासचिव

06.02.2020

सीटू के 50 वर्ष

जिन तक नहीं पहुंचे उन तक पहुंचते हुए

d- geyrk

सीटू के 16वें सम्मेलन ने मजदूर वर्ग से 'नीतियों को बदलने के लिए संघर्ष को नई उंचाई देने' का आहवान किया है। इसे, अभी तक पहुंच से बाहर मजदूरों तक पहुंच कर और उनके रोजमर्रा मुद्दों को सरकार की नीतियों से जोड़कर तथा नीतियों को तय करने वाली राजनीति का पर्दाफाश कर उन्हें उनके वास्तविक दोस्तों और दुश्मनों की पहचान कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

सीटू ने अपने 14 वें सम्मेलन में 'जिन तक नहीं पहुंचे उन तक पहुंचने' का आहवान किया था। तब से इस पर सीटू की जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की सभी बैठकों में बराबर जोर दिया जा रहा है।

वास्तव में इसका क्या मतलब है ? यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है ? हम इसे किस हद तक लागू कर पाये है ? इसे प्रभावी रूप से कैसे अमल में लायें ?

आज, मजदूर वर्ग अभूतपूर्व हमलों की चपेट में है। मजदूरों के वेतन और लाभों पर हमला हो रहा है। उनके कठिन संघर्षों से जीते गये अधिकारों पर हमला है। उनकी संस्कृति, उनके सामाजिक जीवन पर हमला है। वर्गीय पहचान को छिपाकर, विभिन्नता को उभारकर उस पर जोर, एक धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लैंगिक पहचान को दूसरे के विरूद्ध भिड़ाकर मजदूरों की एकता व उनके संघर्षों को कमजोर करना, शासक वर्गों की रणनीति है। बड़े कारपोरेटों, बड़े पूंजीपति वर्ग के लिए अपने मुनाफों को बचाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को आसानी से हड़प कर अपनी दौलत को बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

चूंकि ट्रेड यूनियनें मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे उनके हाथ में अपने हकों के लिए लड़ने का हथियार हैं इसलिए पूंजीपति, ऐसे तमाम हमलों के विरूद्ध सभी तरह के संयुक्त प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ट्रेड यूनियनों को दबा देना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे पैसे, मीडिया तथा राज्य मशीनरी समेत उनके पास उपलब्ध हर संसाधन का प्रयोग करते हैं। ऐसी कोशिशें तब और भी सघन हो जाती हैं। जब पूंजीवादी व्यवस्था संकट में होती है जैसी की वह आज है।

आज, हमारे देश में कुल मजदूरों का केवल लगभग 10 प्रतिशत ही किसी यूनियन में उसके सदस्यों के रूप में संगठनबद्ध है। मजदूरों की संख्या का विशाल बहुमत संगठनबद्ध नहीं है। इसप्रकार, वे पूंजी के बराबर बढ़ते जा रहे हमलों के खिलाफ लड़ने के अपने एकमात्र हथियार से वंचित हैं। हालांकि वे जानते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है लेकिन वे असहाय महसूस करते हैं। उनतक बिना पहुंचे और उन्हें उनके मुद्दों पर संगठित किये बिना, उनमें उनकी संयुक्त ताकत के प्रति जागृति व विश्वास पैदा किये बिना तथा उन्हें संघर्षो में लामबंद किये बिमा, उनमें उनकी संयुक्त ताकत के प्रति जागृति व विश्वास पैदा किये बिना तथा उन्हें संधर्षों में लामबंद किये बिना नवउदारवादी हमलों को परास्त करना और नीतियों को बदल पाना संभव नहीं है।

सीटू का उद्देश्य जैसा कि उसके संविधान में वर्णित है, केवल मजदूरों के वेतन तथा उनके काम के हालातों को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है। सीटू शोषण को समाप्त करना चाहता है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था सहित, समाज के विकास के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित सीटू का दृढ़ विश्वास है कि शोषण को मुनाफे से संचालित मौजूदा पूंजीवादी समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीटू के संविधान में स्पष्ट रूप से समाज को बदलने का उद्देश्य रखा गया है।

ऐसा एक 'अकेले व्यक्ति' या एक छोटे समूह के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सीटू का संविधान कहता है कि केवल वर्ग संघर्ष के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। इसमें मजदूर वर्ग की एक अग्रणी भूमिका और वर्ग संधर्ष के एक माध्यम होने की यह समझदारी ही सीटू को अन्य ट्रेड यूनियनों से अलग दिखाती है।

धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, जेंडर आदि के मौजूदा अंतरों–जिन्हें वर्तमान भाजपा सरकार व शासक वर्ग और बढ़ाने व गहरा करने की कोशिशें कर रहे हैं, से पार जाना ऐसे ताकतवर वर्ग संधर्ष को विकसित करने के लिए जरूरी है। 'नीतियों को बदलने के लिए संधर्षो को उंचाईयों पर ले जाना' वह रास्ता है जो समाज को बदलने के सीटू के संविधानिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर जाता है।

लेकिन ऐसी एकता तब प्राप्त नहीं की जा सकती है जब मजदूर वर्ग का केवल लगभग 10 प्रतिशत ही ट्रेड यूनियन में संगठित है और उनमें से भी एक अत्यन्त छोटे से हिस्से को ही, जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है इसकी स्पष्ट समझ है। श्रम कानून क्यों बदले जा रहे हैं ? वेतन क्यों नहीं बढ़ रहे जबकि कीमतें बढ़ रही है? मजदूरों में भुखमरी क्यों हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों हैं, कुपोषण ग्रस्त क्यों हैं और वे क्यों समुचित इलाज के अभाव में मर जाते हैं जो देश की धन–दौलत पैदा करते हैं।

इंजीनियरों व विद्धानों को रेलवे में ट्रैकमैन के रूप में काम क्यों करना पड़ता हैं ? समाज उनकी सेवाओं का बेहतर प्रयोग कर पाने में असफल क्यों है?

एक बार जब मजदूरों को इस क्यों का उत्तर पता लग जायेगा तो क्या और कैसे की बात भी आयेगी। इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है ? ऐसा कैसे किया जा सकता है ?

8 जनवरी, 2020 – मजदूरों की आम हड़ताल

(फरवरी, 2020 अंक से क्रमशः आगे)

त्रिपुरा

त्रिपुरा में भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली बार, 8 जनवरी 2020 की हड़ताल को आम जनता और खासकर मजदूर वर्ग का व्यापक समर्थन मिला। हड़ताल से पहले, हड़ताल के दिन और बाद में शारीरिक हमलों की धमकियों के बावजूद भी राज्य में बन्द जैसी स्थिति बन गयी थी। इन शारीरिक हमलों में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 126 नाकाबन्दी करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

5.45 लाख से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों ने आम हड़ताल में भाग लिया जिसमें राज्य के एकमात्र औद्योगिक संकुल से 60% से अधिक; लगभग 100% परिवहन में; योजना वर्कर्स 70%; दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के 98%; निर्माण से 45%; शिक्षकों सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय के 70%; 100% मैडीकल रिप्रिजेन्टेटिव्स; 45% राज्य सरकार के कर्मचारी; बीएसएनएल में 50%, बैंक और बीमा में मुकम्मल तौर पर;केंद्र सरकार के कर्मचारियों में 100%; आदि शामिल रहे।

शारीरिक खतरों के बावजूद, अभियान में लगभग 9 लाख लोगों से संपर्क किया गया; सभी उपखंडों में सम्मेलन आयोजित किए गए; 400 आम सभाऐं हुईं; 30,000 पोस्टर, दीवार लेखन, 25,000 पर्चे, कई नुक्कड़ मीटिंगें, बाजार की बैठकें, माइक से प्रचार, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किया गया। हड़ताल की तैयारी और सफलता में सभी बिरादराना जन संगठन गंभीरता से शामिल थे। *(शंकर प्रसाद दत्ता)*

असम

यह हड़ताल राज्य में बड़े पैमाने पर एंव अभूतपूर्व थी। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पूरी तरह से ठप्प हो गई थी। तेल, कोयला, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, जल परिवहन आदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ सुनसान थीं। रेल रोको को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अपने शटर गिरा दिए थे। राज्य में बंद जैसी स्थिति थी। असम की सारी जनता ने व्यापक प्रतिक्रिया दी है।

मजदूर और कर्मचारी स्वःस्फूर्त तरीके से सड़कों पर निकल आए। हजारों की संख्या में हड़तालियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जेएनयू में एबीवीपी की गुण्डागर्दी के खिलाफ नारेबाजी की।

हड़ताल के दौरान, रैलियाँ और नाकाबन्दी की गयी; लगभग 2500 हड़ताली मजदूरों, छात्रों सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राज्य नेताओं और महिला संगठनों के नेताओं को पुलिस ने असम के विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तार किया। *(तपन सरमा)*

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में, 8 जनवरी 2020 की हड़ताल समाज के सभी वर्गों द्वारा समर्थित, बड़ी संख्या में कामकाजी जनता की भागीदारी के साथ मुकम्मल और सफल रही। यह हड़ताल पिछली की तुलना में अधिक व्यापक थी।

उद्योग–वार हड़ताल जूट में 95% थी; चायबागान में 70% से अधिक। बैंकों, बीमा, बीएसएनएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोलकाता पोर्ट, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया और बीपीसीएल आदि में हड़ताल 100% थी। 100% केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारीगण ड्यूटी पर नहीं आये। बिजली क्षेत्र में, हड़ताल की स्थिति में सुधार हुआ। मैडीकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव्स की हड़ताल 100% थी।

कोलकाता और जिलों में; निजी बसें, ट्रक, टैक्सियां पूरी तरह से सडकों से गायब रहीं। परिवहन क्षेत्र में हड़ताल 80% रही। बैरकपुर, दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल, रघुनाथपुर, बक्रेश्वर, फरक्का, कल्याणी, बजबज, दनकुनी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल 100% रही; हल्दिया में यह 70% रही। लंबे समय के बाद, हाईड रोड औद्योगिक क्षेत्रों में सफल हड़ताल हुई।

कोलकाता और जिलों में शॉपिंग मॉल बंद रहे। छोटे व्यापारी, दुकान के रखवाले और बस मालिक भी 23 जिलों में आम हड़ताल में शामिल हुए। छात्रों के संगठनों की हड़ताल के कारण लगभग सभी स्कूल और कोलाज बंद रहे। छात्रों की यूनियनों के सदस्य भी सड़कों पर नाकाबन्दी करने वाले मजदूरों के साथ बने रहे। आईसीडीएस में हड़ताल 75% थी।

कोयला और स्टील में स्थिति कुछ अलग थी। यह कोयले में 30% और स्टील में 27% थी; लेकिन, छोटे और मध्यम स्पंज आयरन के कारखानों में 70% रही।

पहली बार आईटी सेक्टर में 35% की भागीदारी के साथ हड़ताल की गई थी; एसडीएफ कॉल सेंटर में यह 100% थी। असंगठित क्षेत्र की हड़ताल भी व्यापक रूप से फैली हुई थी।

अन्य मेहनतकश तबकों के साथ जुझारु मजदूर सड़कों पर बाधाओं और नाकाबन्दीं का आयोजन कर रहे थे और रेल रोको एवं रास्ता रोको का सहारा लेकर रेल और सड़क सेवाओं को प्रभावित कर रहे थे।

टीएमसी राज्य सरकार ने केंद्र में भाजपा सरकार के साथ मिलकर दमन का सहारा लिया, कई स्थानों पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया; सैकड़ों की गिरफ्तारी की और इन हमलों में टीएमसी के गुंडे भी शामिल हुए। हड़ताली मजदूरों को बदनाम करने के लिए, पुलिस ने खुद बसों में तोड़फोड़ की और मालदा जिले में कारों को जला दिया। *(अनादि साहू)*

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ सीटू यूनियनों के हड़ताली मजदूरों द्वारा संयुक्त रूप से सामूहिक धरना, जुलूस, जनसभाएं आदि आयोजित की। मुख्य कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था जहाँ स्थानीय तिरंगा पार्क में एक सामूहिक धरना का आयोजन किया गया था। दिगलीपुर बाजार में हड़ताली मजदूरों द्वारा बड़े पैमाने पर धरना, प्रदर्शन और जनसभाएँ की गयी; जुलूस ओरलकाता बाजार, हैवलॉक, हट बे, कार निकोबार, कामोर्टा, कच्छल, कैंपबेल बे और द्वीपों के कुछ अन्य हिस्सों में निकाले गए।

ओडिशा

8–9 जनवरी, 2019 की हड़ताल की तुलना में 8 जनवरी 2020 की हड़ताल अधिक सफल रही। औद्योगिक संकुलों को बंद कर दिया गया था। बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा आदि का संचालन ठप्प हो गया। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। आंगनवाड़ी, आशा और एमडीएम मजदूर पूरे राज्य में हड़ताल पर थे। राज्य भर में निजी उद्योगों जैसे रेफ्रेक्ट्रीज, सीमेंट, जेएंडके पेपर मिल, आईडीएल केमिकल्स, सर्वेश रेफ्रेक्ट्रीज, सिवा मिनरल्स, ओसीएल स्पंज और लघु एवं मध्यम उद्योगों के मजदूर हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण परादीप पोर्ट पुरी तरह ठप्प हो गया था। कोयला, इस्पात, नाल्को, एनटीपीसी, नियमित मजदूरों की भागीदारी मामूली थी जबकि ठेका मजदूरों की भागीदारी सौ प्रतिशत थी।

क्लाटा बारसुअन में सार्वजनिक क्षेत्र की खदानों को बन्द कर दिया गया। ओएमसी खदानों में सौ प्रतिशत ठेका मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया। *(रमेश जेना)*

झारखंड

यह अभूतपूर्व हड़ताल और राज्य में एक बंद जैसी स्थिति थी। जनता ने अपना व्यापक समर्थन दिया। राज्य में अनुमानतः 50 लाख मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

कोयला में, हड़ताल सीसीएल और बीसीसीएल में 60% थी; ईसीएल में उत्पादन प्रभावित; कोयला परिवहन और प्रेशण पूरी तरह से पंगु हो गया था। बोकारो स्टील प्लांट के स्थायी मजदूरों की हड़ताल में की भागीदारी कम थी, लेकिन ठेका मजदूरों की की हड़ताल मुकम्मल थी। टाटा औद्योगिक क्षेत्रों में यह टाटा मोटर्स और उससे संबद्ध उद्योगों में आंशिक थी; लेकिन आदित्यपुर–गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर थी। तांबे में, एचसीएल में हड़ताल 100% थी, खदानों में उत्पादन प्रभावित हुआ था। किरीबुरू में, मोहतुबुरु, चिरिया और मनोहरपुर लौह अयस्क खदानों का उत्पादन प्रभावित

हुआ। पलामू लौह अयस्क और नरम पत्थर की खदानें बंद हुईं। सड़क परिवहन कर्मचारियों की भागीदारी प्रभावशाली थी। लंबी दूरी का परिवहन पूरी तरह से ठप्प हो गया था। एचईसी में हड़ताल आंशिक थी।

संथाल परगना में, बीड़ी श्रमिक 100% हड़ताल पर थे; ललमटिया से एनटीपीसी तक कोयला परिवहन प्रभावित रहा। बैंकों और बीमा में मुकम्मल हड़ताल रही; केवल कुछ एसबीआई शाखाएं खुली रहीं। पोस्टल, बीएसएनएल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर थे। राज्य में 3 लाख से अधिक योजना मजदूर मुख्य रूप से आंगनवाड़ी और एमडीएम वर्कर्स हड़ताल पर थे। 10,000 एमआर की हड़ताल मुकम्मल थी। *(प्रकाश विप्लव)*

बिहार

सभी 38 जिलों में 10 लाख से अधिक मजदूर और कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। यह राज्य में बंद जैसी स्थिति थी। छात्रों के संगठनों द्वारा शैक्षिक संस्थान बंद के आह्वान को पूरे बिहार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। किसान और खेत मजदूरों द्वारा आहुत किए गए ग्रामीण बंद को भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा जवाब मिला। हाजीपुर, बिहिता, फतुहा और बरह में औद्योगिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और इसे पूरी तरह से सफल बनाया।

रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और बिहार राज्य ऑटो रिक्शा चालक संघ ने सड़क परिवहन प्रणाली को राज्य में पूरी तरह से पंगु बना दिया। जिला प्रषासन के समक्ष प्रदर्शन का आयोजन करते हुए राज्य भर में आंगनवाड़ी, आशाओं और एमडीएम वर्कर्स द्वारा हड़ताल की गयी। बैंक, बीमा और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ–साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में यह हड़ताल पूरी तरह से मुकम्मल रही। हड़ताल और लामबंदी में महिला मजदूरों की भागीदारी पुरुष मजदूरों की तुलना में बहुत अधिक थी। *(अनुपम कुमार)*

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों को धता बताते हुए, 16 जिलों में हड़ताल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वाराणसी औद्योगिक संकुल में हड़ताल मुकम्मल रही।

बैंक, बीमा, डाक विभाग, दूरसंचार, केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों में हड़ताल 60–90% थी। हजारों बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। बीएचईएल झांसी में, हड़ताल 90% से अधिक थी। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी, आशाओं, मिड–डे–मील के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। मेडिकल प्रतिनिधियों की हड़ताल मुकम्मल थी वाराणसी औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल सफल रही।

अधिकांश जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्यालयों के सामने जुलूस और रैलियां निकाली गईं और प्रदर्शन किए गए। आयोजित की गयी प्रत्येक सार्वजनिक सभाओं में 1000–3000 की संख्या में मजदूरों की भागीदारी रही। *(प्रेम नाथ राय)*

दिल्ली

दिल्ली–एनसीआर में हड़ताल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद और गाजियाबाद के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में पूरी तरह से मुकम्मल हुई।

साहिबाबाद साइट 4 में ऑटो गियर, पीवीजी, अनुपम प्रोडक्ट्स, होली स्विच, इंड्योर, कूपर स्टैंडर्ड, सीईएल, एटलस साइकिल्स (हरियाणा) लिमिटेड, एमबीडी, एसएस पैकर्स के साथ–साथ मोहन नगर, हापुड़ रोड जैसे प्रमुख उद्योग पूरी तरह से बन्द थे। भारी बारिश के बावजूद, औद्योगिक क्षेत्रों में सफल हड़ताल की रैलियाँ आयोजित की गईं जिनमें 1000 से 1500 मजदूरों ने भाग लिया।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, हड़ताल कुल सेक्टर 2, 3, 4, 7, 8, 11, 63, 64, 67, होजरी कॉम्प्लेक्स, एनएसईजैड फेज –2, छिजारसी, हबीबपुर, देवला, तिगरी आदि में आंषिक से पूर्ण तक रही। 250–500 हड़ताली मजदूरों के साथ रैलियों को आयोजित किया गया।

पूर्वी दिल्ली में, पटपड़गंज, झिलमिल कॉलोनी, लोनी रोड, सीमा पुरी के औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल कुल मिलाकर आंशिक से पूर्ण तक रही। गाजीपुर के केंद्रीय भंडारण निगम में हड़ताल मुकम्मल रही। औद्योगिक क्षेत्रों में 100–200 हड़ताली मजदूरों की रैलियाँ आयोजित की गईं।दक्षिण दिल्ली में, ओखला फेस–1 और 2 में हड़ताल लगभग 50% थी

और ओखला फेस–3 में यह 40% थी। सड़क पर धरने का आयोजन 1 घंटे से अधिक समय तक किया गया था जिसके कारण सड़क पर नाकाबंदी रही थी।

उत्तरी दिल्ली में, बवाना, बादली, बोल्डर और कुछ अन्य क्षेत्रों में हड़ताल कुल मिलाकर आंशिक से पूर्ण तक रही थी। बादली औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से बंद था। बवाना की रैलियों में लगभग 1000 मजदूर शामिल हुए और बादली में 300 मजदूर शामिल हुए।

बीमा और बैंकों में हड़ताल मुकम्मल थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं आसपास के अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने बैज पहनकर और गेट मीटिंग करके हड़ताल का समर्थन किया।

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने शहीदी पार्क से आईटीओ चौक तक एक प्रभावशाली रैली निकाली जिसे राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। *(अनुराग सक्सेना)*

पंजाब

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के 60 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य फेडरेशनों के आह्वान पर; परिवहन, बिजली, मनरेगा, निर्माण, वन, योजना, गाँव चौकीदारों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, बैंकों और बीमा कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र आदि के लाखों मजदूर पंजाब और चंडीगढ़ में हड़ताल पर चले गए। कई स्वतंत्र ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन भी हड़ताल में शामिल हुए।

संयुक्त और स्वतंत्र विरोध रैली और प्रदर्शन आयोजित किए गए। 150 से अधिक स्थानों पर रोडवेज को बाधित किया गया। सीटू द्वारा लुधियाना में और एआईकेएस द्वारा मनसा में रेल रोको किया गया; और अमृतसर में ट्रेड यूनियनों, छात्रों और अन्य जन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से सड़क की नाकाबंदी की गयी।

जिला लुधियाना में रायकोट और सुधर, जिला संगरूर में सुनाम और मनसा शहर पूरे दिन बंद रहे। लुधियाना, होशियारपुर, बठिंडा, मोगा, अमृतसर, शहीद भगत नगर, जालंधर, संगरूर, बरनाला, मनसा, पठानकोट, पटियाला, फिरोजपुर और चंडीगढ़ हड़ताल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। *(रघुनाथ सिंह)*

जम्मू और कश्मीर

डोडा जिले में, दुलहस्ती पॉवर स्टेशन, पाकुड़ल, किरू–कवार, हाइड्रो एचई परियोजना में लगे 400 से अधिक निर्माण मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और बर्फबारी में भी रैली आयोजित की। रामबन जिले में, सावलकोट एचई परियोजना की एचसीसी कंपनी के लगभग 500 मजदूरों ने हड़ताल की और रैली में भाग लिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। पुंछ जिले में, माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगे 200 मजदूरों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लिया।

जम्मू जिले में, 500 निर्माण मजदूर, आशाओं, मिड–डे–मील, लोडिंग और अनलोडिंग मजदूर; बीमा, बैंक और रेलवे कर्मचारियों ने जम्मू में प्रेस क्लब पर, विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। श्रीनगर में, लगभग 400 बागवानी श्रमिकों, आंगनवाड़ी, निर्माण, बिजली कर्मचारियों ने प्रतिबंधों और धारा 144 लगाने के बावजूद भी संयुक्त विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कथुआ जिले में, 600 निर्माण, बॉडर रोडस्, किसान, रेहबरी तालिम शिक्षक, आशा, एमडीएम मजदूरों ने विरोध रैली में भाग लिया और डीसी को ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान

कपड़ाः झालावाड़ जिले में भवानी मंडी टैक्सटाइल मिल के सभी 5000 और रिंगस टेक्सटाइल मिल के सभी 1,600 मजदूर पूर्ण हड़ताल पर थे। **सड़क परिवहनः** आरएसआरटीसी में एटक और इंटक की मुख्य यूनियनें हड़ताल में शामिल नहीं हुईं। सीटू यूनियन ने अपनी सीमित क्षमता के साथ सीकर, चूरू, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में सड़क परिवहन को प्रभावित किया था। **ऑटोसः** श्रीगंगानगर में 1500 श्रमिकों के साथ सीटू संघ और सीकर में 600 कर्मचारी हड़ताल पर थे। **एम.आर.ः** राज्य भर में सभी 5000 हड़ताल पर थे। **औद्योगिक क्षेत्रः** जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में मिनी रत्ना पीएसई, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) सहित 6 इकाइयों में सीटू यूनियनें हड़ताल पर थीं। **रावत भाटा एटम पावर प्लांट–** केवल 12,000 ठेका कर्मचारी हड़ताल पर थे। **कॉपरः** राजस्थान

के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हड़ताल पूर्ण थी। **ईंट भट्ठाः** श्रीगंगानगर में 300 ईंट भट्ठों के 30,000 और हनुमानगढ़ में ईंट भट्ठों के 2000 मजदूर हड़ताल पर थे। **निर्माणः** अधिकांश जिलों में निर्माण श्रमिक विभिन्न तादाद में हड़ताल पर थे। **सीमेंटः** कोई हड़ताल नहीं। **एनसीआर में नीमरानाः** जापानी जोन में डैकिन, जहाँ पिछली हड़ताल में पुलिस की गोलीबारी हुई, अवकाश घोषित किया और कारखाने बंद कर दिए। नीमराना एडीएम ने स्थानीय निकाय चुनाव की याचिका पर सभी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया। **एफसीआई और राज्य के गोदामः** श्रीगंगानगर में 2000 और हनुमानगढ़ में 16000 हेड–लोडर हड़ताल पर थे।

जिलावारः श्रीगंगानगर (9 तहसीलों सहित में), हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में हड़ताल व्यापक थी; जयपुर में आंशिक रही। श्रीगंगानगर में व्यापारी भी आम हड़ताल में शामिल हुए। जयपुर सहित 13 जिलों में रैलियां निकाली गईं। *(वी.एस. राणा)*

मध्य प्रदेश

एनएफएल गुना, ग्वालियर डिस्टिलैरी, त्रिप्ती डिस्टिलैरी, एंटारी स्लीपर फैक्ट्री, नीमच में 3 फैक्ट्रियों और इंदौर में कुछ कारखानों में 100% मजदूर हड़ताल पर रहे; रीवा में 3 सीमेंट कारखानों, भारी इंजीनियरिंग वर्क्स और हाईटेक कारखाने में 100% हड़ताल रही; और बालाघाट निजी मैंगनीज कारखानों में 100% हड़ताल रही थी।

कोयला में, डब्ल्यूसीएल में हड़ताल 70–80%, एसईसीएल में 40% और एससीएल में 20% थी। सड़क परिवहन में 21 जिलों में हड़ताल 60% से 90% थी। आंगनबाड़ी द्वारा 35 जिलों में तथा आशा वर्कर्स द्वारा 22 जिलों में योजना मजदूरों की हड़ताल हुई। राज्य में 35 कृषि मंडियों में हड़ताल हुई। एमआर द्वारा यह मुकम्मल हड़ताल थी। बैंक, बीमा और आयकर में प्रभावी हड़ताल हुई। प्रतिरक्षा कारखानों में हड़ताल 20% से 35% थी। पीडब्लूडी, पीएचई और राज्य सरकार के सिंचाई विभागों में 5 जिलों में सीआइटीयू यूनियन ने हड़ताल का नेतष्त्व किया गया।

सीटू यूनियन की प्रभावी नाकाबन्दी ने बारगंवा में हिंडाल्को के प्रवेष द्वार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ और बीएचईएल भोपाल के प्रवेश द्वार को सभी यूनियनों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जिससे उत्पादन पर असर पड़ा।

अधिकांश जिलों में धारा 144 लागू होने के बावजूद, हड़ताली कर्मचारियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं और प्रदर्शन आयोजित किए। *(प्रमोद प्रधान)*

छत्तीसगढ़

राज्य में, हड़ताल लगभग पूर्ण थी। बैंक, बीमा, फार्मा हड़ताल में 100% थी; बाल्को में 95%, कोयला 60–70%, सरकारी कर्मचारी 90% से अधिक, आँगनवाड़ी वर्कर्स 80%। सभी यूनियनों ने एकजुट होकर भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी गेटों के समक्ष प्रदर्शन किया। *(एम.के. नंदी)*

महाराष्ट्र

8 जनवरी 2020 की हड़ताल पिछले वर्षों में हुई हड़तालों से कहीं अधिक व्यापक रही है। मुंबई और रायगढ़ में, महिंद्रा, लार्सन टुब्रो, सीईएटी, भारत पेट्रोलियम और ओएनजीसी में हड़ताल थी। दशकों के बाद मझगांव डॉक जहाज निर्माण यार्ड में मुकम्मल हड़ताल हुई। पुणे के ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र में, महिंद्रा और बजाज में हड़ताल थी। अल्फा लावल, सैंडविक और एटलस कोपको के मजदूरों ने भी काम बन्द किया। हड़ताल से नासिक औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। औरंगाबाद में, बजाज, गुडईयर टायर्स और अन्य प्रमुख कारखानों में हड़ताल हुई।

8 जनवरी को औद्योगिक मजदूरों का सामूहिक जमावड़ा पिछले सभी रिकॉर्डों को पार कर गया। संभवतः महाराष्ट्र में पहली बार, सभी प्रमुख औद्योगिक केंद्रों जैसे कि नासिक, औरंगाबाद, पुणे और कोल्हापुर में एक साथ 15,000 से अधिक मजदूर शामिल हुए। मुंबई और सोलापुर में 15,000 से अधिक मजदूरों की एक–एक रैलियां हुईं। आजाद मैदान में एक विशाल रैली हुई, जिसमें हजारों आंगनवाड़ी वर्कर्स, बैंक कर्मचारी, डॉक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी आदि शामिल थे। नागपुर, जालना, रायगढ़ और ठाणे में बड़े पैमाने पर भीड़ थी।

शाहपुर में, एआईकेएस और सीटू द्वारा संयुक्त रूप से, 3000 से अधिक मजदूरों–किसानों ने मुंबई नासिक फ्रीवे पर रास्ता रोको किया। ग्रामीण नासिक जिले के कई स्थानों पर और अहमदनगर, पुणे, सांगली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, जालना, बुलढाणा, वर्धा और नंदुरबार में भी एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू को शामिल करके रास्ता रोको और धरने हुए।

हड़ताल के अभियान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका राजनीतिक चरित्र था। मजदूरों की माँगों के चार्टर के अलावा, अभियान ने जेएनयू छात्रों पर लोकतांत्रिक विरोधी मोदी–शाह शासन द्वारा हमलों की निन्दा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हड़ताल के पैम्फलेट्स ने सीएए और एनसीआर जैसे गंभीर मुद्दों को उठाकर कामकाजी जनता को विभाजित करने के शासन के प्रयासों की आलोचना की; भाजपा–आरएसएस की सांप्रदायिक खेल योजना के खिलाफ; और संविधान की रक्षा करने पर केन्द्रित रहा।

हड़ताल अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने मोदी सरकार के हमले का सामना करने और बीपीसीएल और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रस्तावित निजीकरण जैसे विशिष्ट मुद्दों पर इसे परास्त करने के लिए ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के बाद की अवधि में निरंतर आधार पर एकता को मजबूत करने की आवश्यकता व्यक्त की। *(विवेक मोन्टेरिओ)*

गोवा

भाजपा राज्य सरकार के शत्रुतापूर्ण रवैये के बावजूद एक बंद जैसी स्थिति बनी हुई थी।

गुजरात

गुजरात ने सूरत, अहमदाबाद आदि में हड़ताल गतिविधियों की हड़बड़ी देखी, विशेषकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसके अलावा, बैंक और बीमा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल मुकम्मल रही थी।

गुजरात में, कई जिलों में, जहाँ कोई अन्य ट्रेड यूनियन मौजूद नहीं है, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशाओं ने न केवल भाजपा राज्य सरकार की धमकियों को धता बताते हुए हड़ताल में भाग लिया, बल्कि प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए पहल की थी।

कामकाजी महिलाओं की एआईसीसी का 12वाँ सम्मेलन

अमृतसर, 6–7 अप्रैल 2020

– कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का 12वाँ सम्मेलन 6–7 अप्रैल, 2020 को पंजाब के अमृतसर में होगा। प्रत्येक के लिए प्रतिनिधि शुल्क 500 रुपये है।

– राज्यवार अधिसूचित कोटा में संबंधित राज्यों की महिला राष्ट्रीय कार्यसमिति और सीटू की जनरल कौंसिल के सदस्य शामिल हैं। साथ ही सीटू राज्य समितियों की कामकाजी महिलाओं के अध्यक्ष/महासचिव और प्रभारी भी भाग लेंगे।

– प्रतिनिधिमंडल में निर्माण, ईंट भट्ठा, वस्त्र/परिधान/सिलाई, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं; पारंपरिक उद्योग जैसे हथकरघा, कॉयर, काजू आदि; वृक्षारोपण, बीड़ी, नगरपालिका; सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/आईटी/आईटीईएस में कार्यरत ठेका मजदूर; निजी अस्पताल; निजी शिक्षकों; परिवहन; दवा उद्योग; एसईजैड; घरेलू; घर–आधारित उद्योग, कढ़ाई, माचिस और पटाखे आदि से प्रतिनिधि होने चाहिए।

सभी महिला यूनियनों जैसे आंगनवाड़ी, आशा और एमडीएम वर्कर्स आदि को कुल प्रतिनिधिमंडल के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

(फरवरी 2020 अंक से क्रमशः आगे)

दिल्ली

ट्रेड यूनियनों के केन्द्रीय नेताओं ने दिल्ली में रैली को सम्बोधित किया

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

शिमला की बर्फवारी में रैली

राजस्थान

जयपुर में

उत्तर प्रदेश

लखनऊ में

बिहार

झारखंड

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

त्रिपुरा

राजधानी शहर अगरतला में एक सुनसान सड़क

पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ऑफिस जाते हुए,
उन पर हड़ताल के दिन भाजपा के गुण्डों ने हमला किया

8 जनवरी 2020 की हड़ताल

पश्चिम बंगाल

हड़ताल के दिन – कोलकाता की सुनसान सड़कें

कोलकाता में हड़ताल रैली

श्रम मंत्री के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक

ईपीएफ और ईएसआई के तहत सेवा वितरण पर

आर. करुमलायन

केंद्रीय श्रम मंत्री ने पहले चरण में, (1) ईएसआईसी, (2) ईपीएफओ और (3) सीएलसी (सी) द्वारा सेवा वितरण पर 'कार्यान्वयन निगरानी सेल' की स्थापना के बारे में सुझाव के लिए 12 फरवरी 2020 को एक बैठक में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं को आमंत्रित किया। सीटू की ओर से मैं बैठक में शामिल हुआ।

सीटू की प्रस्तुति

बैठक में सीटू की प्रस्तुति पहले से ही कवर किए गए लोगों को सेवा की डिलीवरी के अलावा मौजूदा कवरेज/गैर–कवरेज; ईएसआई और ईपीएफ को मजबूत करने पर केंद्रित थी।

सीटू ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो मूल रूप से अच्छी तरह से काम कर रही ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा की मौजूदा प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और अच्छी तरह से काम करने का है, उनके वित्तीय संसाधनों के संवर्धन का है। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने का एकमात्र साधन योगदान की दरें हैं जो दुर्भाग्य से कम हो रही है। ईएसआई में योगदान पहले से कम हो गया है – 01.07.2019 से नियोक्ता का योगदान कर्मचारी को देय वेतन का 4.75% से कम होकर 3.25% और कर्मचारी का 1.75% से कम होकर 0.75% हो गया है। इसी तरह, ईपीएफ के मामले में अब यह सामाजिक सुरक्षा कोड में मौजूदा 12% की दर को बिगाड़ने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। सीटू ने माँग की कि दोनों मामलों में पिछली योगदान दरों की अनुमति दी जानी चाहिए।

कवरेज के सवाल पर, सीटू ने कहा कि प्रवर्तन को धीमा नहीं किया गया था और अधिनियमों के निशुल्क प्रवर्तन की अनुमति दी गई थी, ईएसआई और ईपीएफ कवरेज दोगुनी हो गई होती। प्रमाणित करने के लिए, सीटू ने पावर–लूम सेक्टर में ईपीएफ के गैर–कवरेज पर आरपीएफसी (शोल्हापुर) की रिपोर्ट का उल्लेख किया। इसलिए, संबंधित कानून के अनुसार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन को सक्रिय करना होगा।

एक और मुद्दा यह है कि पीएफ ट्रिब्यूनल में न्यायिक रिक्तियां समय पर नहीं भरी जा रही हैं। कई रिक्तियां लंबे समय से मौजूद हैं। सीटू ने सरकार से सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाने का आग्रह किया।

उपरोक्त आरम्भिक टिप्पणियों के साथ, सीटू ने सुझावों के साथ मौजूदा विशिष्ट कमियों पर एक लिखित नोट प्रस्तुत किया।

ईपीएफओ पर

मुख्य लक्ष्य सभी पात्र प्रतिष्ठानों और उनके सभी श्रमिकों का नामांकन होना चाहिए। इसे नियोक्ताओं की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। श्रम विभाग/ईपीएफओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि ये ठीक से लागू हों।

नियमित निरीक्षण एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ''निरीक्षण नहीं'' की वर्तमान प्रणाली मदद नहीं करती है। जब कोई मजदूर या ट्रेड यूनियन अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाए तो निरीक्षण आदि को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को त्वरित कदम उठाने चाहिए। अधिकारियों द्वारा जब ये कदम उठाए जाऐं शिकायतकर्ता मजदूरों/ट्रेड यूनियनों को सम्पर्क में रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम एक महीने की समय सीमा होनी चाहिए। इसमें, मजदूरों की गणना करने का काम खुद इंस्पेक्टर के पहली बारे जाने पर ही किया जाना चाहिए। उसके बाद अभिलेखों का सत्यापन हो।

ईपीएफ के मौजूदा ग्राहकों में से बहुत से रिकॉर्ड में अपने नाम और जन्म तिथि के बारे में अनगिनत समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो आधार और अन्य दस्तावेजों के साथ मेल नहीं खाते हैं। लिंकेज असंभव हो गया है, खासकर ठेका मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों और अन्य जैसे कि लोडिंग और अनलोडिंग श्रमिकों के लिए ऐसी समस्याएं हैं। सीटू ने इस समस्या को हल करने के लिए एक उचित तरीका विकसित करने की माँग की।

- कटौती की गयी सदस्यता और नियोक्ता के हिस्से को न भेजना एक गंभीर समस्या है। अनेक सेवामुक्त होने जा रहे मजदूरों को अपने खातों का निपटान करना मुश्किल लगता है।

- अग्रिमों/अंतिम निपटान आदि के आवेदनों का निपटारा अब ऑनलाइन किया जाता है। ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में 'हेल्प–डेस्क' होना चाहिए। अब यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप असंख्य समस्याएं होती हैं।
- ग्राहकों द्वारा दायर किए गए आवेदनों में किसी भी कमी को बिना किसी देरी के इंगित किया जाना चाहिए। शिकायतें यह हैं कि आवेदन तथ्यहीन आधार पर अंतिम क्षण में भी लौटा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि 'शून्य लंबित' दिखाने के लिए भी।
- शिकायत प्रक्रिया में तत्काल बदलाव की जरूरत है। ग्राहकों की शिकायतों को ठीक से नहीं देखा जाता है और बार–बार की गई शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिलता है।
- पंजीकृत ट्रेड यूनियनों/क्षेत्रीय समिति के सदस्यों/सीबीटी सदस्यों की फरियादों/शिकायतों का जवाब देने के लिए एक सुनिश्चित तंत्र होना चाहिए। अभी तो यहाँ तक कि सीबीटी सदस्यों को भी शायद ही कोई जवाब मिले या एक पावती भी।

ईएसआईसी पर

जब 5 साल पहले, ईएसआईसी ने पूरे देश में कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया, तो इसका स्वागत किया गया। लेकिन अभी भी जरूरत के अनुसार चिकित्सा/प्रशासनिक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है। नतीजतन, नए कवर किए गए मजदूरों के पास ईएसआई योजनाओं के लाभ नहीं पहुँच पा रहे हैं।

- मजदूर अंधेरे में ही रहते हैं कि उनके नियोक्ताओं द्वारा योगदान समय पर दिया गया है या नहीं। वे तब प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं, जब उन्हें इलाज से वंचित कर दिया जाता है। जैसा कि ईपीएफ में लागू किया गया है, ईएसआईसी भी एसएमएस के जरिए बीमित व्यक्तियों (आईपी) को अपडेट कर सकता है।
- जब बन्दी/लॉक–आउट/निलंबन जैसी घटनाओं की वजह से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता के योगदान को कम से कम नौ महीने तक जारी रखा जाना चाहिए, ताकि उस आधार पर उपचार से इनकार न किया जा सके।
- वर्तमान में, डिस्पेंसरी स्थापित करने के लिए क्षेत्र के आकार के आधार पर दूरी का कोई मानदंड नहीं है। परिणामस्वरूप, मजदूरों को 40/50 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा करनी होती है। क्षेत्र के आकार के साथ–साथ आईपी घनत्व के आधार पर भी कुछ मानक होना चाहिए।
- चिकित्सा व्यवसायी को प्रति बीमित व्यक्ति (आईपी) के शुल्क का भुगतान एक निश्चित समय पर न होने के कारण वे ईएसआई पैनल के डॉक्टरों के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए अनिच्छुक हो गए। अब दर में संशोधन किया गया है। लेकिन ईएसआईसी ने समाचार मीडिया/विज्ञापन के माध्यम से इसका व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया है। तो लाभ बीमित व्यक्तियों तक नहीं पहुँचता है।
- ईएसआईसी की मंजूरी के बिना जारी किए गए 16 नवंबर 2016 के परिपत्र में यह स्पष्ट करने की माँग की गई है कि जहाँ भी ईएसआईसी अस्पतालों में सभी सुपर स्पेशिएलिटी ट्रीटमेंट (एसएसटी) सेवाएं हैं, मरीजों को इस तरह के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में नहीं भेजा जाएगा। कोई दूरी या परिधि का उल्लेख नहीं किया गया है। नतीजतन, रोगियों को परेशान किया जाता है/उपचार से इन्कार कर दिया जाता है।
- बीमित व्यक्तियों को अपने हितलाभ की पात्रता के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। क्षेत्रीय भाषाओं में एक साधारण बीमित व्यक्ति हैंडबुक के माध्यम से उस जागरूकता को प्रचारित किया जा सकता है। इस तरह की हैंडबुक की अनुपस्थिति में, सख्त आवश्यकता के समय, वे एक से दूसरी जगह दौड़ते हैं। कुछ ईएसआईसी कार्यालय उन्हें गुमराह भी करते हैं।

महत्वपूर्ण रेफरल उपचार के लिए निर्णय लेने में अनुचित देरी के कारण; बीमित व्यक्ति को यह मानने के लिए छोड़ दिया जाता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन रोगियों को निजी दलालों के बीच फेंक दिया जाता है।

श्रम मंत्री ने राय को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया और श्रम कानूनों की संहिताओं पर विचार सुनने के लिए शीघ्र ही एक और बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।

(आर. करुमलायन सीटू केंद्र में राष्ट्रीय सचिव हैं)

उद्योग एवं क्षेत्र

ry o xl

कोच्चि में हुआ तेल व पेट्रोलियम मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वैशन

दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला

स्वदेश देव रॉय

बी.पी.सी.एल. के मजदूर इस ऑयल रिफाइनिंग व मार्केटिंग के विशाल सार्वजनिक उपक्रम को बेचे जाने के मोदी सरकार के फैसले के विरूद्ध संयुक्त कार्रवाईयों में उतरे हुए हैं। इनमें 28 नवम्बर 2019 को हुई भारी हड़ताल भी शामिल है। उनकी राष्ट्रीय फेडरेशनों–ए.आइ.पी.डब्ल्यू.एफ., एन.एफ.पी.डब्ल्यू. तथा पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई. ने 26 अक्टूबर को मुंबई में, 20 नवम्बर को नई दिल्ली में तथा 22 दिसम्बर, 2019 को कोलकाता में एक के बाद एक तीन राष्ट्रीय कवेंशन आयोजित किये हैं।

इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के मजदूरों ने आम तौर पर और बी.पी.सी.एल. के मजदूरों ने खासतौर पर 8 जनवरी 2020, की मजदूरों की आम हड़ताल में अभूतपूर्व भागेदारी की। 28 नवम्बर और 8 जनवरी की हड़तालों में बी.पी.सी.एल. मजदूरों की भारी भागेदारी ने बी.पी.सी.एल. का निजिकरण करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ मजदूरों के लड़ने के संकल्प को प्रदर्शित किया है। मजदूरों ने मोदी सरकार की तमाम धमकियों व डराने की कोशिशें तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रयासों से प्रबंधको द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों से लिए गये निषेधाज्ञा आदेशों का सामना करते हुए हड़तालों में हिस्सा लिया।

कोच्चि राष्ट्रीय कन्वेंशन

9 फरवरी 2020 को तीनों राष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा संयुक्त रूप से एक और राष्ट्रीय कन्वेंशन बी.पी.सी.एल. की कोच्चि रिफाइनरी के परिसर में आयोजित किया गया। तेल व प्राकृतिक गैस की सभी शाखाओं–उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन व मार्केटिंग का तथा ओ.एन.जी.सी., ओ.आइ.एल., गेल, आइ.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल, एम.आर.पी.एल. , बामेर लॉवरी, पावर हंस व अन्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सारे देश से प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। यह महत्वपूर्ण रहा कि ओ.एन.जी.सी., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल, आइ.ओ.सी.एल. यानी देश के तेल क्षेत्र की अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम हब मुंबई से 50 प्रतिनिधियों ने इम कन्वेंशन में भाग लिया।

कन्वेंशन ने सभी ट्रेड यूनियनों से संबद्ध कोच्चि रिफाइनरी के मजदूरों को पिछले चार महीनों से विभिन्न तरह से आंदोलन व लामबंदी के माध्यम से लगातार जारी रखे गये विरोध कार्यक्रम के लिए बधाई दी। यही नहीं कन्वेंशन ने प्रदर्शनों, जुलूसों, विरोध मार्चो आदि के आयोजन के द्वारा बी पी सी एल के मजदूरों के संधर्ष का समर्थन करने के लिए केरल की जनता को भी सलामी दी। इसके अतिरिक्त कन्वेंशन ने एक बार फिर गर्व के साथ बी पी सी एल के निजिकरण के खिलाफ केरल की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को तथा केरल के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को याद किया।

सीटू महासचिव तपन सेन ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया केरल के इंटक अध्यक्ष चन्द्रशेखरन; केरल सीटू के महासचिव इलामारम करीम; तथा तीनों फेडरेशनों के नेताओं ने कन्वेंशन को संबोधित किया। सर्वसमति से पारित किये गये कोच्चि घोषणापत्र के पेश मसविदे पर 23 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। सीटू के सचिव तथा आयल सैक्टर के इंचार्ज स्वदेश देव रॉय ने समापन भाषण दिया।

विशाल जुलूस व कन्वेंशन

कोच्चि रिफाइनरी के मजदूरों, उनके परिवार के सदस्यों, कोच्चि के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के मजदूरों व कन्वेंशन में शामिल हो रहे प्रतिनिधियों समेत 4000 मजदूरों का एक विशाल जुलूस कोच्चि की सड़कों पर 10 किलोमीटर मार्च करते हुए जन कन्वेंशन में बदल गया जिसे कन्वेंशन को संबोधित करने वाले राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने संबोधित किया।

बी.पी.सी.एल. अंत नहीं शुरूआत है

कन्वेंशन के कोच्चि घोषणापत्र में नोट किया गया कि तेल व पेट्रोलियम सेक्टर के लिए मोदी सरकार की नीति हर तरह से विनाशकारी है। यह, एक ओर से अपस्ट्रीम व डाऊनस्ट्रीम दोनों ही क्षेत्रों में उपक्रमों को भारी कर्ज में दबाकर तेल सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय व संचालन ताकत को कमजोर कर रही है तथा दूसरी ओर निजीक्षेत्र को खुलेआम बढ़ावा देने वाली नीतियों को आगे बढ़ाकर उन्हें प्रतियोगितात्मक रूप में कमजोर कर नुकसान पहुंचा रही है। सरकार की आखिरी मंशा वित्तीय रूप से इन्हें इतना कमजोर करने की है ताकि तेल क्षेत्र के देसी–विदेशी निजी टाइकूनों को इन्हें औने–पौने दाम पर लेने में सुविधा हो।

उदाहरण के लिए ओ.एन.जी.सी. के साथ खेजी गई तेल व गैस फील्डस की क्षमता को एक्सप्लोरेशन के लिए निजी खिलाड़ियों को सौंपा जा रहा है, एच पी सी एल और हमेशा से बीमार गुजरात सरकार की तेल व पेट्रोलियम कंपनी का टेक ओवर करने के लिए मजबूर कर ओ.एन.जी.सी. को कर्ज में डुबोया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में अंबानियों व अन्य निजी खिलाड़ियें को लाभ देकर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरीज को उनके मुकाबले बुरी स्थिति में डालना भाजपा सरकार के बुरे व राष्ट्र विरोधी कदमों की कलई खोलता है। उदारीकरण की ओ.ए.एल.पी. (ओपन एकरेज लाइसेंसनिंग पॉलिसी) के तहत पहले चार चक्रों में निजी क्षेत्र ने प्रमुख फील्डस् पर कब्जा जमा लिया है : वेदान्ता–51, ओ आइ एल–21 व ओ एन जी सी–17।

इस बीच विदेशी तेल कंपनियां भारत में उत्पादन और शोधन सेक्टर में गहरे धुस रही हैं। सऊदी आरामको और आबू धाबी एडनोक महाराष्ट्र के रत्नगिरि में प्रस्तावित एकीकृत रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स की 6 करोड टन प्रति वर्ष की क्षमता में 50 प्रतिशत की इक्विटी हासिल करने वाली है।

ऐसी नीतियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के साथ ही इस सेक्टर के मजदूरों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करने के साथ ही ईंधन की निर्भरता के परिणामस्वरूप कम उपभोग के संदर्भ में जनता पर भारी बोझ थोप देंगी। इसे सफल नहीं होने दिया जा सकता है तथा तेल क्षेत्र के ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस खतरनाक खेल का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी।

समूचे ऊर्जा सेक्टर के मजदूरों को एकजुट होना चाहिये

कन्वेंशन ने नोट किया कि ऊर्जा सेक्टर के सभी हिस्से सरकार की विनाशारी नीतियों के चलते अलग–अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह नोट करना रोचक है कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम जो फिलहाल निजीकरण की तलवार के नीचे है उसका संबध जिन सैक्टरों (ऑयल व पेट्रोलियम, कोयला, पॉवर व रिपिंग एंड कंटेनर बिजनेस) से है वे पहले से ही मोदी सरकार के दैत्याकार दरबारी पूंजीपतियों–अंबानी व अडानी के बिजनेस के दायरे में हैं।

जारी आर्थिक संकट ने सार्वजनिक क्षेत्र ऊर्जा उद्योगों को भी संकट की गिरफ्त में धकेल दिया है। आठ प्रमुख सैक्टरों की सूची में जिनमें वृद्धि को गहरा धक्का लगा है उनमें से पाँच–कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व बिजली उर्जा क्षेत्र से हैं। परिस्थिति चुनौतिपूर्ण है और वह समूचे उर्जा क्षेत्र के मजदूरों के एकीकृत संयुक्त प्रतिरोध संधर्षों के लिए अवसर भी प्रदान कर रही है।

कोच्चि कन्वेंशन में पारित कार्रवाई कार्यक्रम

- 20–21 अप्रैल, 2020 को बी.पी.सी.एल. की सभी इकाईयों में दो दिन की राष्ट्रव्यापी संयुक्त हड़ताल। 4 अप्रैल, 2020 तक नोटिस दे दिया जाना है।
- बी पी सी एल के हड़ताली मजदूरों की एकजुटता में 20 अप्रैलए 2020 को शेष सभी तेल व पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के मजदूरों का सामूहिक कैजुअल अवकाश तथा 21 अप्रैल 2020 को विशाल संयुक्त एकजुटता प्रदर्शन।
- सभी तेल व पेट्रोलियम केन्द्रों खासतौर पर मुंबई, कोलकता, गुवाहाटी (या असम के अन्य उचित केन्द्र पर), चैन्नै, कोच्चि, बैंगलोर व दिल्ली (एनसीआर) में मार्च महीने के भीतर ऑयल व पेट्रोनियम मजदूरों के संयुक्त कन्वेंशन होंगे।
- निजीकरण का विरोध करने का संदेश जनता में फैलाने के लिए, निजीकरण के खतरों से लोगों को अवगत कराने के लिए संबंध्ति राज्यों के सभी इलाकों में मार्च महीने में नुक्कड़ बैठकों व वाहन जत्थों का आयोजन।

- अप्रैल 2020 में महीने की पहली तारीख से 15 अप्रैल 2020 तक जहाँ भी बी.पी.सी.एल. के प्रतिष्ठान कार्यरत है वहां यूनियनों को केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की भागेदारी के साथ जन कन्वेंशनों का आयोजन करना चाहिये।
- 20–21 अप्रैल की अखिल भारतीय हड़ताल के लिए किये जाने वाले भारी व व्यापक अभियान में क्षेत्रीय, स्थानीय व इकाई स्तर पर कन्वेशन/बैठके, गेट सभायें, नारेबाजी, प्रदर्शन, जुलूस, परचा वितरण, पोस्टरों आदि के साथ चलाया जाये।
- 15 से 20 अप्रैल तक बी.पी.सी.एल. रिफाइनरी गेट, सी ओ एंड रीजनल मुख्यालयों, बॉटलिंग प्लांटों, डिपुओं व अन्य जगहों पर सारे देश में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रमिक समूह धरना दिया जायेगा।
- एन.एफ.पी.डब्ल्यू., ए.आइ.पी.डब्ल्यू.एफ. व पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आई. के बैनर तेल व पेट्रोलियम मजदूरों का अगला राष्ट्रीय कन्वेंशन 3 मई 2020 को तीनो फेडरेशनों के संबद्धों द्वारा कोच्चि में किया जाना है इसमें निजीकरण का प्रतिरोध करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल समेत कार्रवाई का आगामी कार्यक्रम तय किया जायेगा।
- बी.पी.सी.एल. के मजदूरों के निजीकरण विरोधी संधर्ष के समर्थन में सभी तेल व पेट्रोलियम केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में एन.एफ.पी.डब्ल्यू, ए.आर.पी.डब्ल्यू.एफ. तथा पी.जी.डब्ल्यू.एफ.आइ. के संबद्ध 15 से 20 अप्रैल, 2020 के दौरान एकजुटता अभियान व आंदोलन करेंगे।

योजना मजदूर

संसद के समक्ष एन.सी.एल.पी. स्टॉफ का धरना

नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (एन.सी.एल.पी.) स्कीम के 7 राज्यों से आये लगभग 1000 स्टॉक सदस्यों ने योजना के लिए बजट आंवटन बढ़ाने, मानदेय के रूप में दिये जाने वाले पारिश्रमिक को बढ़ाकर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के बराबर किये जाने की माँगों को लेकर 14 फरवरी, 2020 को संसद के सामने जंतर–मंतर पर दिन भर धरना दिया।

9–14 वर्ष तक के बाल श्रम के शिक्षा के माध्यम से पुनर्वास की योजना–एन.सी.एल.पी. 21 राज्यों के 270 जिलों में चल रही है जिसमें लगभग 35,000 लोग स्टॉक के रूप में वर्षों से वालंटियर के रूप में कार्यरत हैं जिन्हें मामूली मानदेय दिया जाता है। बालश्रम के एक नये सर्वे के बाद बहुत से जिलों में योजना बंद होने जा रही है। जिससे इसमें कार्यरत स्टॉक की नौकरी खतरे में है।

रेलवे

ए.आइ.एल.आर.एस.ए. का संसद के समक्ष धरना

19 फरवरी, 2020 को देश भर से आये लगभग 3000 रेलवे लोकोमेन ट्रेन पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट व शंटर्स ने अपने परिवारों के साथ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉक

फार्म–4

1• प्रकाशन का पता	:	बी टी रणदिवे भवन 13–ए राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002
2•प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3• मुद्रक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
पताः	:	बी टी रणदिवे भवन 13–ए राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002
4• प्रकाशक का नाम	:	तपन सेन
क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
5• संपादक का नाम	:	के. हेमलता
क्या भारत का नागरिक हैं	:	हाँ
6• कुल पूंजी के एक प्रतिशत से ज्यादा के हिस्सेदार समाचारपत्र व साझीदारों का नाम व पता	:	सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स 13–ए, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–110002

हस्ताक्षर
तपन सेन
प्रकाशक

एसोसिएशन के बैनर तले नई दिल्ली के अंबेडकर भवन से जंतर–मंतर तक मार्च किया रैली निकाली, रेलवे मंत्रालय के सामने धरना व सभा की।

धरने का उद्धाटन सीटू महासचिव तपन सेन ने किया। एकजुटता में आइ आर डी एफ डीजल मोर्डनाईजेशन वर्क्स पटियाला ने भी धरने व रैली में शिरकत की।

ए.आइ.एल.आर.एस.ए ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लकर यह रैली व धरना किया जिसमें आर ए सी 1980 के फार्मूले के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी रनिंग अलाउंस कर रिवीजन; काम के घंटों में कमी कर 10 धंटे करना और फिर 8 धंटे 15 दिन में 90 धंटे की सीमा तथा काम के हालात; पे रिवीजन के हिसाब से उच्च पे व पेंशन; एन पी एस को रद्द करने; लंबित उत्पीड़न के मुद्दों, एसोसिएशन की मान्यता तथा रेलवे के निजीकरण के विरोध की मांगे शामिल थीं।

(योगदानः एम एन प्रसाद)

ईपीएस-95

कम्यूटेशन नियम बदल गया

ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के पेंशन कम्यूटेशन संबंधी मुद्दों पर करीब पांच साल तक सीबीटी में चर्चा हुई। व्यक्तिगत मजदूरों के उदाहरणों के साथ सीटू ने इसमें हुए अन्याय के मुद्दे को उठाया था।

ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन कम्यूटेशन के तहत, कम्यूटेशन मिलने के बाद पेंशन से कटौती अनिश्चित काल के लिए जारी थी। कम्यूटेशन राशि 100 महीने की है। फिर भी, कई मामलों में यह 300 से अधिक महीनों तक जारी रहा। बीच में, कम्यूटेशन की व्यवस्था को ही हटा लिया गया था।

कई बार लंबी चर्चा और फैसलों के बाद, अब 20 फरवरी 2020 को, सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्रकाशन की तारीख से 15 साल बाद कटौती बंद कर दी जाएगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

सा.का.नि.132(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 है।

   (2) यह योजना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में पैरा 12 के पश्चात निम्नलिखित पैरा को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"***12ख. संराशीकरण प्रदान करने के मामलों में सामान्य पेंशन की पुन:बहाली.*** – इस योजना के तत्कालीन पैरा 12क के अधीन 25 सितम्बर, 2008 को या इससे पहले पेंशन संराशीकरण का लाभ प्राप्त कर चुके सदस्यों के संबंध में सामान्य पेंशन, ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पुन:बहाल की जाएगी।"

[फा. सं. आर-15011/01/2019-एसएस-II(भाग)]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

फिर से इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगों के लिए, जिनकी पेंशन 15 साल बाद भी काटी जा रही थी, उनका वह पैसा हमेशा के लिए खत्म हो गया।

सीटू ने माँग की कि 15 साल पूरे होने के बाद काटे गए पैसे वापस किए जाएं और कम्यूटेशन करने की सुविधा फिर से शुरू की जाए।

– एकेपी

सीटू के पचास साल

कामकाजी महिलाएं
समानता के लिए और भेदभाव के खिलाफ लड़ो

ए.आर. सिन्धु

उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य

सीटू के संघर्ष के पचास वर्षों के दौरान समाज में और ट्रेड यूनियन आंदोलन के में पितृसत्ता, शोषण, असमान व्यवहार और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ महिला मजदूरों के समझौताविहीन संघर्ष शामिल हैं। क्रांतिकारी मार्ग में आगे बढ़ते हुए, सभी प्रकार के विचलनों और व्यसनों से लड़ते हुए, सीटू ने सामाजिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानव जाति की आधी आबादी के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है।

सीटू संविधान ने सही दृष्टिकोण निर्धारित किया है *''सीटू का मानना है कि मजदूर वर्ग के शोषण को केवल, उत्पादन, वितरण और विनिमय के सभी साधनों का सामाजीकरण करके और एक समाजवादी राज्य स्थापित करने से ही समाप्त किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्श को मजबूती से पकड़े हुए, सीटू सभी तरह केशोषण से समाज को मुक्त करने के लिए खड़ा है।''* सीटू का तात्पर्य है *''जाति के आधार पर जैसे कि छुआछूत, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के उन्मूलन के लिए''*।

यह दो बातों को स्पष्ट करता है – एक, समाज को सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का कार्य, महिलाओं की मुक्ति के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, जो समाज का आधा हिस्सा हैं। दूसरे, वर्तमान पूंजीवादी–सामन्ती समाजिक व्यवस्था के तहत, महिलाओं की बुनियादी समस्याओं को कभी भी पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य के साथ, अपने स्थापना सम्मेलन में, सीटू ने एक प्रस्ताव के माध्यम से, महिला मजदूरों को संगठित करने और उनकी समस्याओं को उठाने का कार्य निर्धारित किया था। जल्द ही यह एहसास हुआ कि किसी भी सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है जैसा कि मद्रास (चेन्नई) में 1979 में बुलाए गए कामकाजी महिलाओं के पहले सम्मेलन की रिपोर्ट में वर्णित है। *''सीटू को एक विशेष सम्मेलन बुलाने का निर्णय लेना पड़ा क्योंकि यह पाया गया कि कामकाजी महिलाओं की शिकायतें उपेक्षित थीं; सरकार उदासीन थी; नियोक्ता शत्रुतापूर्ण थे; और यहाँ तक कि ट्रेड यूनियन भी उनकी माँगों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। मजदूर वर्ग ने जो कई हड़तालें लड़ीं, उनमें केवल कुछ ऐसे उदाहरण थे जब कामकाजी महिलाओं की विशेष माँगों को तरजीह दी गई थी। यह भी पाया गया कि महिलाओं को यहाँ तक कि उद्योगों और व्यवसायों में भी, जहाँ उनकी मौजूदगी एक बड़े तबके के रुप में थी, शायद ही यूनियनों के प्रमुख निकायों में प्रतिनिधित्व दिया गया था।''*

सीटू के संस्थापक अध्यक्ष बी.टी. राणदिवे ने कहा कि, *''जब तक महिलाओं का दस्ता यूनियनों को संगठित करने में और नेतृत्वकारी भूमिका नहीं निभाता है, तब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन अपनी पूर्ण उँचाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। हजारों महिलाएं हड़ताल के संघर्षों में भाग लेती हैं, जेल और दमन का सामना करती हैं, पुरुष मजदूरों व कर्मचारियों के साथ तकलीफों से गुजरती हैं। लेकिन वे यूनियनों में स्थिति हासिल करने से दूर हैं।''*

इस प्रकार, ऑल इण्डिया कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वुमेन्स, एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) का गठन, ट्रेड यूनियन मंच से महिला मजदूरों के मुद्दों को उठाने, सीटू में बड़ी संख्या में महिला मजदूरों को संगठित करने, उन्हें प्रषिक्षित करने और उन्हें नेतृत्व की स्थिति में लाने के उद्देश्य से किया गया था। विमल राणदिवे इसकी पहली संयोजक थी।

कामकाजी महिलाओं के आंदोलन को आगे बढ़ाना

पिछले चालीस वर्षों के दौरान, एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) कामकाजी महिलाओं के बीच बहुत काम कर सका है और महिला मजदूरों की समस्याओं को सबसे आगे ला सका है। तब से उजागर करने के काबिल कई उपलब्धियां हैं।

समान पारिश्रमिक, पदोन्नति में समान अवसर, मातृत्व और गर्भपात की छुट्टी, पितृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ और बालगृह (क्रेच), ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेक, महिला कामगारों के लिए अलग शौचालय, रात में काम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, काम पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे आदि के मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर लिया गया। सीटू इन मुद्दों को सबसे आगे लाने, मजदूरों और समाज को संवेदनशील बनाने और कई कानूनों एवं नियमों को बनाने में बड़ा कारक बना है।

सीटू, भारत में महिलाओं की उप–समिति/महिला विंग बनाने वाली पहली ट्रेड यूनियन है। अब केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, बीमा, बीएसएनएल के कर्मचारियों, साथ ही एटक, इंटक और एचएमएस सहित अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने महिला विंग/उप समितियों का गठन किया है।

महिलाओं को संगठित करने के सचेत प्रयासों के साथ, ऐसे क्षेत्रों को लक्षित करना जहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं, ... % से बढ़कर 1991 में 12% हो गई; 1998 में 17.75% तक; और 2018 में 33.3%। सीटू की विभिन्न कमेटियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक स्पष्ट सुधार देखा गया है। वर्तमान में, सीटू में अध्यक्ष सहित 8 महिला पदाधिकारी हैं। सीटू की दो राज्य कमेटियों में महिला अध्यक्ष हैं। कई जिला कमेटियों में महिला सचिव और अध्यक्ष हैं। लगभग सभी राज्य कमेटियों में महिला पदाधिकारी और राज्य कमेटी सदस्य हैं।

महिला कैडरों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर दो बार, सीटू के राज्य नेताओं को शामिल करते हुए किया गया। चर्चा और प्रतिक्रिया के आधार पर, गलत प्रथाओं को, यदि कोई हो, तो ठीक करने के लिए संगठनात्मक उपाय किए जाते हैं। हमारे देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंतरिक शिकायत कमेटी बनाने वाला सीटू एकमात्र ट्रेड यूनियन है।

योजना मजदूरों का आंदोलन

सीटू ने बड़ी संख्या में पारंपरिक क्षेत्रों जैसे बीड़ी, वृक्षारोपण आदि से महिला मजदूरों को संगठित किया है। सीटू की पहल पर आंगनवाड़ी, आशाओं और मिड डे मील, पैरा शिक्षकों आदि जैसे योजना मजदूरों के सभी क्षेत्रों के महिला मजदूरों को ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्यधारा में लाया गया है।

अस्सी के दशक की शुरुआत में, एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) द्वारा आंगनवाड़ी मजदूरों का एक फेडरेशन एआईएफएडब्ल्यूएच का गठन किया गया। अब, एआईएफएडब्ल्यूएच 24 राज्यों में फैली लगभग 5 लाख की सदस्यता के साथ एक मजबूत फेडरेशन के रुप में विकसित हो गया है और संघर्षों में सबसे आगे रहा है जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सहित कई उपलब्धियां हासिल हुईं। एआईएफएडब्ल्यूएच और एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू), अन्य योजना मजदूरों, विशेष रूप से आशा और एमडीएम मजदूरों को संगठित करने में सहायक रहे हैं। योजना मजदूरों के संघर्षों ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी सीटू की उपस्थिति दर्ज की है और ग्रामीण इलाकों में अपना प्रभाव फैलाने में मददगार हुआ है। वर्गीय मंच के तहत महिलाओं को संगठित करके और वर्गीय पहचान के साथ उनके संघर्ष ने – संघर्षों में और संगठन में कई रूढ़ियों को तोड़ दिया – और कामकाजी महिलाओं के आंदोलन में नया आत्मविश्वास लाया है। इसने न केवल अधिक नेताओं और कैडरों को ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाने में मदद की है, बल्कि महिलाओं के अवैतनिक श्रम, विशेष रूप से देखभाल–कार्य को भी विचार विमर्श के केन्द्र में ला दिया है। अब, योजना श्रमिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर एक जुझारु और गतिशील ताकत हैं, जो वर्ग शोषण के साथ–साथ ट्रेड यूनियन मंच से सामाजिक उत्पीड़न को उठा रहे हैं।

आलोचात्मक समीक्षा

लेकिन समाज में पितृसत्तात्मक और सामंती रवैया इतना अधिक प्रचलित है कि प्रतिरोध भी उतना ही मजबूत है। सीटू द्वारा इसकी कामकाजी महिलाओं के मोर्चे में कार्यों और वैचारिक स्पष्टता की समय–समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

'कामकाजी महिलाऐं एक वर्गीय परिप्रेक्ष्य' एक कमीशन पेपर स्पष्ट करता है ***''पहले और सर्वप्रथम, हमें यह तसदीक करनी चाहिए कि कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर जिन कार्यों को हमने खुद पर लागू किया है वे वर्ग संघर्ष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। यह उन महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो हमारे समाज का एक 'कमजोर तबका' है।***

सीटू के हर सम्मेलन में समीक्षा की गई है। 6वें और 10वें सम्मेलनों में विशेष चर्चाऐं की गयीं। 10वें सम्मेलन में 'कामकाजी महिलऐं एक वर्गीय परिप्रेक्ष्य' और 13वें सम्मेलन में 'कामकाजी महिलाओं को संगठित करने' पर कमीशन पेपर्स पर चर्चा करके अपनाया गया। इसके अलावा, 2003 में एक सीटू के राज्य नेतृत्व के साथ–साथ एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) की राष्ट्रीय कार्यशाला का अयोजन किया गया। का आयोजन किया गया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर दो बार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का अयोजन किया गया था।

संगठन पर भुवनेश्वर दस्तावेज और कोझिकोड दस्तावेज, दोनों में ही कामकाजी महिलाओं के बीच काम की आत्मालोचनात्मक समीक्षा की है। संगठन पर कोझीकोड दस्तावेज (2018) कहता है, *"यौन उत्पीड़न सहित कामकाजी महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों को हमारी कई यूनियनों ने नहीं उठाया है। वे माँग–पत्रों में भी शामिल नहीं हैं। महिला मजदूरों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में अधिकांश यूनियनों में महिलाओं की उपसमिति का गठन नहीं किया गया है। कामकाजी महिलाओं के बीच काम को केवल महिला कैडरों की जिम्मेदारी माना जाता है। कक्षाओं में लिंगभेद से जुड़े मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। जो पितृसत्तात्मक रवैया, समाज में प्रचलित है, वह संगठन के भीतर मौजूद है। इन कमजोरियों पर काबू पाने से ही कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम को आगे बढ़ाने और मजदूरों के नए तबकों के बीच सीटू के विस्तार में मदद मिलेगी।"*

बैठकों का समय, महिलाओं के लिए उपयुक्त न होना, इन कमजोरियों में शामिल है, बैठक में भाग लेने के लिए महिला कॉमरेडों को यात्रा व्यय का भुगतान न करना, बातचीत की टीम में उन्हे शामिल न करना आदि अभी भी संगठन के भीतर प्रचलित हैं जिन्हें पूरी तरह से दूर करने की आवश्यकता है।

गोल्डन जुबली वर्ष में आयोजित सीटू के 16वें सम्मेलन ने, एक कमीशन पेपर में शोषण की वर्तमान बढ़ती स्थिति में सामाजिक उत्पीड़न के सवाल पर चर्चा की, और कुछ कार्यों की जिम्मेदारी को लिया गया है।

वर्तमान चुनौतियां और कार्य

नवउदारवाद शोषण में वृद्धि करने और मुनाफाखोरी के लिए, हमारे देश में आगे मौजूद, प्रतिगामी सामंती, रुढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था और जाति, धर्म, लिंग जातीय के आधार भेदभाव जैसी परम्पराओं आदि, सभी साधनों का उपयोग करता है। देश में सामाजिक उत्पीड़न, उसी अनुपात में या असमानताओं में वृद्धि से भी अधिक वृद्धि कर रहा है; पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेषकर जब से मौजूदा सरकार एक ओर मुक्त बाजार पर आधारित नवउदारवादी नीतियों का बेरोकटोक पालन करते हुए सब कुछ का वस्तुकरण कर रही है और दूसरी ओर सामंती, पितृसत्तात्मक, जातिवादी प्रणाली पर आधारित प्रतिगामी विचारधारा 'हिंदुत्व' पर जोर दे रही है। शासक वर्ग, न केवल अपने राजनीतिक हित, बल्कि अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक सामंती अवशेषों जैसे कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव आदि का उपयोग करते हैं।

हमारे समाज में वर्गीय शोषण, सामाजिक उत्पीड़न के रूप में कई गुना और आपस में इस कदर गड्डमड्ड होकर प्रकट होता है कि इसे अलग करना कठिन होता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति और घर पर अवैतनिक श्रम को कई व्यवसायों में विशेष रूप से देखभाल–कार्य और सेवाओं में बढ़ाया जा रहा है और इसका उपयोग अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। सेवाओं में कैजुअलाइजेशन ऐसे गैर–मान्यता प्राप्त व्यवसायों के माध्यम से किया जाता है, जो स्कीम वर्कर्स के रूप में होते हैं। *'यूएन के एक उच्च स्तरीय पैनल द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में महिलाओं द्वारा किया गया 51% से अधिक कार्य अवैतनिक है और उसे राष्ट्रीय आंकड़ों में नहीं गिना जाता है। आईएलओ के अनुसार, अवैतनिक देखभाल–कार्य और गृहकार्य जो हम कर रहे हैं, देखभाल की लागत को सब्सिडी दे रहा है और अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन इसे कभी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है।* यह अनुमान है कि अवैतनिक घरेलू कार्य विनिर्माण, वाणिज्य और परिवहन क्षेत्रों की तुलना में अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि महिलाओं का वेतन, ग्रामीण क्षेत्रों में समान काम करने वाले पुरुषों की तुलना में 34% कम है, और हमारे देश में शहरी क्षेत्रों में यह 19% कम है। भारत में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर सबसे ज्यादा है।

एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू ने चर्चा करके इन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का फैसला किया है और माँग की है कि इन सभी अवैतनिक नौकरियों को जीडीपी की गणना के हिसाब में लगाया जाए और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान और उनके शोषण का आकलन और मान्यता दी जाए।

सीटू सम्मेलन ने अवैतनिक श्रम के इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है, महिलाओं के शोषण की जड़, बेरोजगारी के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जो कि काम में महिलाओं की कम भागीदारी, महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व अत्याचार एवं हिंसा और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व आदि में परिलक्षित होता है पर व्यापक अभियान के बाद, अंतर्राष्ट्रीय कामकाजी महिला दिवस के अवसर पर एक जुझारु कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। सीटू के स्वर्ण जयंती वर्ष में, 6 मार्च 2020 (चूंकि 8 मार्च से रविवार है) को, एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू) के नेतृत्व में, हजारों महिला मजदूरों द्वारा पूरे देश में 'जेल भरो' संघर्ष का आयोजन करेंगी। यह भारत में महिलाओं की मुक्ति के संघर्ष में एक नए चरण को चिह्नित करेगा।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	uoEcj 2019	fnlEcj 2019
vk/k iznsk	xq.Vj	302	303
	fot;ckMk	307	309
	fo'kk[kkiÝkue	310	316
vle	MeMek frulf[k;k	296	303
	xokgkVh	290	292
	ycd flYpj	286	285
	efj;kuh tkjgkV	275	281
	jxkikjk rst iqj	269	268
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	366	367
p.Mhx<	p.Mhx<	322	325
NÝkhlx<	fHkykbZ	346	344
fnYyh	fnYyh	309	311
Xkkvk	xkvk	332	343
Xkqtjkr	vgenkckn	301	299
	Hkkouxj	307	309
	jktdkV	307	309
	lqjr	292	289
	oMknjk	292	295
gfj;k.kk	Qjhnkckn	288	289
	;eukuxj	311	312
fgekpy	fgekpy çns'k	281	283
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	290	292
>kj[k.M	ckdkjks	320	321
	fxfjMhg	361	370
	te'kniqj	381	380
	>fj;k	378	380
	dksMek	408	406
	jkph gfV;k	412	418
dukVd	cqyxke	315	324
	cqxyq#	305	308
	gcyh /kkjokM	348	353
	ejdjk	320	326
	esyqj	321	323
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	327	332
	eq.MkD;ke	332	337
	fDoykU	368	372
e/; çns'k	Hkksikky	344	345
	fNUnokM+k	326	329
	bUnkSj	298	297
	tcyiqj	337	337

jkT;	dsn	uoEcj 2019	fnlEcj 2019
महाराष्ट्र	मुम्बई	322	322
	ukxiqj	407	405
	ukfld	377	380
	iq.k	358	357
	'kksykiqj	350	347
mMhlk	vkSjaxkcknqj&rkyqdk	346	346
	jkmjdsyk	337	342
ikfMpfj	ikfMpfj	326	334
iatkc	vesfrlj	356	357
	tkyU/kj	334	340
	ywf/k;kuk	309	317
jktLFkku	vtesj	297	300
	HkhyokM+k	307	308
	t;iqj	325	326
rfeyukMq	pUuS	288	295
	dks;EcVwj	300	307
	dUuwj	345	349
	enqjkbZ	318	323
	lsye	308	311
	fr#fpjkiYyh	310	322
rsyaxkuk	xkednkojh[kkuh	346	348
	gSnjkckn	275	278
	okjaxy	328	332
f=iqjk	f=iqjk	277	280
mÝkj çns'k	vkxjk	375	377
	xkft;kckn	349	350
	dkuiqj	357	361
	y[kuÅ	357	358
	okjk.klh	355	356
if'pe cxky	vklulky	356	356
	nkftZfyax	287	290
	nqxkZiqj	336	338
	gfYn;k	368	369
	gkoM+k	302	305
	tkyikbZxqM+h	296	295
	dksydkrk	299	303
	jkuhxat	309	316
	flyhxqM+h	302	302
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**328**	**330**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; फोनः (011) 23221306
  फैक्सः (011) 23221284

रेल मंत्रालय के समक्ष एआईएलआरएसए का धरना

(रिपोर्ट पृ. 21)

बीपीसीएल के निजीकरण के खिलाफ कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ. 19)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 05/03/2020)

इंकलाब जिन्दाबाद – क्रान्ति अमर रहे

दिल्ली बम मुकदमे की पूरी सुनवायी के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त न्यायालय में प्रवेश करते हुए और बाहर जाते हुए ''इंकलाब जिन्दाबाद'' का नारा लगाते थे। जब मजिस्ट्रेट ने इस नारे का अर्थ पूछा तो उन्होने लिखित जबाव प्रस्तुत किया जिसके निष्कर्ष दो पैराग्राफ 7 और 8 नीचे दिए गए हैं। यह आधुनिक समावेशी भारत के बारे में भगत सिंह और उनके साथियों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

"(7) मैं, भगत सिंह से निचली अदालत में, पूछा गया था कि 'क्रांति' शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है। उस सवाल के जवाब में, मैं कहूंगा कि क्रांति में एक खूनी संघर्ष अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, और न ही व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए इसमें कोई जगह है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को बदलना होगा। समाज का सबसे आवश्यक अंग होने के बावजूद, उत्पादकों या मजदूरों की मेहनत के फल को शोषकों द्वारा लूटा जाता है और उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। एक ओर किसान जो सभी के लिए अनाज उगाता है, वह अपने परिवार के साथ भूखा रहता है; एक बुनकर जो विश्व बाजार तक में कपड़े की आपूर्ति करता है, उसके पास खुद के और अपने बच्चों के शरीर को ढंकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं होता है; शानदार महल बनाने वाले राजमिस्त्री, लुहार और बढ़ई मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं; और दूसरी ओर पूँजीवादी शोषक, समाज के परजीवी, अपने पर करोड़ों उड़ाते हैं। इस तरह की भयानक असमानताएं और अवसरों की थोपी गयी असमानताऐं, अराजक हालात तक बढ़ रही हैं। यह स्थिति नहीं चल सकती; और यह स्पष्ट है कि समाज की वर्तमान व्यवस्था ज्वालामुखी के मुहाने पर है और शोषकों के नादान बच्चे भी करोड़ों शोषितों के बच्चों की तुलना में कम खतरनाक ढ़लान पर नहीं चल रहे हैं। इस सभ्यता की सम्पूर्ण इमारत को, यदि समय रहते नहीं बचाया गया तो उखड़ जाएगी। इसलिए, एक आमूल परिवर्तन आवश्यक है; और यह उन लोगों का कर्तव्य है जो समाजिक आधार पर समाज को पुनर्गठित करने की इस जरुरत को महसूस करते हैं। जब तक यह नहीं किया जाता है और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का और राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों के शोषण को यानी छद्मवेषी साम्राज्यवाद को समाप्त किए बिना मानवता पर छाये पीड़ा और नरसंहार के खतरे को रोका नहीं जा सकता है और तब तक युद्धों को समाप्त करने और सार्वभौमिक शांति के युग में प्रवेश करने की बात करना कोरा पाखंड ही है। क्रांति से हमारा तात्पर्य एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना से है, जिसे इस तरह की टूटन का खतरा न हो और जिसमें सर्वहारा वर्ग की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, और जिसके परिणामस्वरूप मानवता को पूँजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी युद्धों से मुक्त करके विश्व महासंघ की स्थापना हो सके।

(8) यह हमारा आदर्श है, और इस विचारधारा के साथ अपनी प्रेरणा के लिए हमने उचित और जोरदार चेतावनी दी है। यदि, जैसे भी, इसे अनदेखा किया जाता है और सरकार की वर्तमान व्यवस्था प्राकृतिक शक्तियों के रास्ते में बाधा बन रही है जो पूरी तरह से खत्म होनी है, तो एक गंभीर संघर्ष के द्वारा सभी बाधाओं को उखाड़ फेंकना होगा, और क्रांति के आदर्श के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित करने के लिए प्रयास करने होगे। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक गम्भीर जन्म सिद्ध अधिकार है। मजदूर समाज का वास्तविक निर्वाहक होता है। जनता की संप्रभुता ही मजदूरों की अंतिम नियति है।

इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हम किसी भी दुःख का स्वागत करेंगे जो हमें दिया जा सकता है। क्रांति की इस बलिवेदी के लिए हम अपनी जवानी को हवन सामग्री के रूप में लाऐ हैं; इसके लिए, इतनी शानदार वजह के लिए कोई भी बलिदान बहुत महान नहीं है। हम संतुष्ट हैं; हम क्रांति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

''क्रांति अमर रहे।''

हस्ताक्षरित /–

भगत सिंह

बटुकेश्वर दत्त

06–06–1929

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**